

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.संख्या-11015/98/2021-एफडी
दिनांक: 13 दिसंबर, 2021

आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी,
सादर नमस्कार,

सबसे पहले, मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

कृपया ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के विषय पर मेरे द्वारा दिनांक 20 सितंबर, 2021 को लिखे गये पत्र का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को राज्यों को एक व्यापक परामर्श जारी किया। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य रूप से द्विमासिक आवृत्ति पर न्यूनतम 6 बैठकें करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया था।

यह भी सहमति हुई थी कि ग्राम सभा की बैठकों में जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, के संबंध में विकास के लिए व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए; जिला/ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों (ग्रुप ए/बी) द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके विभाग की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों, के बारे में अवगत कराया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे, लाइन विभाग के अधिकारियों को, निर्देशित चर्चा की सुविधा के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में, अपने विभागों से संबंधित मुद्दों/योजनाओं पर मानकीकृत प्रस्तुतीकरण भी करना आवश्यक है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण क्षेत्र के माध्यम से पहचाने गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के अंतराल के अस्तित्व पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इन अंतरालों को कैसे पाटना है, इसकी पहचान की जा सके।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि इन बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम 10% रखा जाए और इस कोरम के भीतर महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता न्यूनतम 30% रखी जाए। ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा / महिला सभा / बालसभा की बैठकों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अग्रिम रूप से पहचान की जा सके और ग्राम सभाओं के दौरान चर्चा के लिए लाया जा सके।

इसके अलावा, पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित किया गया है; और इस दिशा में, स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सहमत होंगे कि जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और निधियों को एक साथ लाने की (अभिसरण की) तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक जन योजना अभियान के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभाओं में विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया है।

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

(2)

आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा राज्य में, ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के 47%, पेयजल विभाग से मात्र 18%, पशुपालन विभाग से 31%, शिक्षा विभाग से 40%, ग्रामीण विकास विभाग से 53%, महिला एवं बाल विभाग से 66 %, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से मात्र 15 %, स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग से 49% जल संसाधन विभाग से मात्र 2% और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से 'शून्य' अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों ने भाग लिया। यह देखा जा सकता है कि ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों की भागीदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आप सहमत होंगे कि ऐसा अभिसरण जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तभी संभव होगा जब कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इससे न केवल ग्राम सभा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण आबादी में भी उत्साह और भागीदारी पैदा होगी जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

तदनुसार, यह अनुरोध है कि अपने राज्य के सभी संबंधित विभागों को ग्राम सभा की बैठकों में लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें, ताकि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(गिरिराज सिंह)

श्री मनोहर लाल खट्टर
माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा,
4वीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय,
सैक्टर-1 चंडीगढ़, हरियाणा-160001

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.संख्या-11015/98/2021-एफडी
दिनांक: 13 दिसंबर, 2021

आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी,
सादर सम्स्कार,

सबसे पहले, मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

कृपया ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के विषय पर मेरे द्वारा दिनांक 20 सितंबर, 2021 को लिखे गये पत्र का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को राज्यों को एक व्यापक परामर्श जारी किया। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य रूप से द्विमासिक आवृत्ति पर न्यूनतम 6 बैठकें करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया था।

यह भी सहमति हुई थी कि ग्राम सभा की बैठकों में जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, के संबंध में विकास के लिए व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए; जिला/ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों (ग्रुप ए/बी) द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके विभाग की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों, के बारे में अवगत कराया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे, लाइन विभाग के अधिकारियों को, निर्देशित चर्चा की सुविधा के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में, अपने विभागों से संबंधित मुद्दों/योजनाओं पर मानकीकृत प्रस्तुतीकरण भी करना आवश्यक है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण क्षेत्र के माध्यम से पहचाने गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के अंतराल के अस्तित्व पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इन अंतरालों को कैसे पाटना है, इसकी पहचान की जा सके।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि इन बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम 10% रखा जाए और इस कोरम के भीतर महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता न्यूनतम 30% रखी जाए। ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा / महिला सभा / बालसभा की बैठकों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अग्रिम रूप से पहचान की जा सके और ग्राम सभाओं के दौरान चर्चा के लिए लाया जा सके।

इसके अलावा, पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित किया गया है; और इस दिशा में, स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सहमत होंगे कि जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और निधियों को एक साथ लाने की (अभिसरण की) तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक जन योजना अभियान के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभाओं में विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया है।

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

(2)

आंकड़ों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में, ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के 65%, पेयजल विभाग से मात्र 9%, पशुपालन विभाग से 28%, शिक्षा विभाग से 66%, ग्रामीण विकास विभाग से 25%, महिला एवं बाल विभाग से 54 %, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से मात्र 13 %, स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग से 35% जल संसाधन विभाग से मात्र 5% और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से 'शून्य' अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों ने भाग लिया। यह देखा जा सकता है कि ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों की भागीदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आप सहमत होंगे कि ऐसा अभिसरण जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे। इससे न केवल ग्राम सभा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण आबादी में भी उत्साह और भागीदारी पैदा होगी जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

तदनुसार यह अनुरोध है कि अपने राज्य के सभी संबंधित विभागों को ग्राम सभा की बैठकों में लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें, ताकि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

सादर

भवदीय,
(Signature)

(गिरिराज सिंह)

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय,
रायपुर-492001

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.संख्या-11015/98/2021-एफडी
दिनांक: 13 दिसंबर, 2021

आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी,
मादर नमस्कार

सबसे पहले, मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

कृपया ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के विषय पर मेरे द्वारा दिनांक 20 सितंबर, 2021 को लिखे गये पत्र का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को राज्यों को एक व्यापक परामर्श जारी किया। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य रूप से द्विमासिक आवृत्ति पर न्यूनतम 6 बैठकें करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया था।

यह भी सहमति हुई थी कि ग्राम सभा की बैठकों में जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, के संबंध में विकास के लिए व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए; जिला/ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों (ग्रुप ए/बी) द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके विभाग की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों, के बारे में अवगत कराया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे, लाइन विभाग के अधिकारियों को, निर्देशित चर्चा की सुविधा के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में, अपने विभागों से संबंधित मुद्दों/योजनाओं पर मानकीकृत प्रस्तुतीकरण भी करना आवश्यक है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण क्षेत्र के माध्यम से पहचाने गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के अंतराल के अस्तित्व पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इन अंतरालों को कैसे पाटना है, इसकी पहचान की जा सके।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि इन बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम 10% रखा जाए और इस कोरम के भीतर महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता न्यूनतम 30% रखी जाए। ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा / महिला सभा / बालसभा की बैठकों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अग्रिम रूप से पहचान की जा सके और ग्राम सभाओं के दौरान चर्चा के लिए लाया जा सके।

इसके अलावा, पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित किया गया है; और इस दिशा में, स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सहमत होंगे कि जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और निधियों को एक साथ लाने की (अभिसरण की) तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक जन योजना अभियान के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभाओं में विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया है।

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

(2)

आंकड़ों से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में, ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के 31%, पेयजल विभाग से 20%, पशुपालन विभाग से 24%, शिक्षा विभाग से 27%, ग्रामीण विकास विभाग से 40%, महिला एवं बाल विभाग से 24 %, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से मात्र 6 %, स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग से 29% जल संसाधन विभाग से 'शून्य' और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से 'शून्य' अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों ने भाग लिया। यह देखा जा सकता है कि ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों की भागीदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आप सहमत होंगे कि ऐसा अभिसरण जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तभी संभव होगा जब कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इससे न केवल ग्राम सभा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण आबादी में भी उत्साह और भागीदारी पैदा होगी जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

तदनुसार, यह अनुरोध है कि अपने राज्य के सभी संबंधित विभागों को ग्राम सभा की बैठकों में लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें, ताकि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(गिरिराज सिंह)

श्री जयराम ठाकुर
माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
कमरा न. ई-100 आर्मसडेल बिल्डिंग,
हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171002

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.संख्या-11015/98/2021-एफडी
दिनांक: 3 दिसंबर, 2021

आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी,
सादर -महोदय,

सबसे पहले, मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

कृपया ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के विषय पर मेरे द्वारा दिनांक 20 सितंबर, 2021 को लिखे गये पत्र का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को राज्यों को एक व्यापक परामर्श जारी किया। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य रूप से द्विमासिक आवृत्ति पर न्यूनतम 6 बैठकें करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया था।

यह भी सहमति हुई थी कि ग्राम सभा की बैठकों में जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, के संबंध में विकास के लिए व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए; जिला/ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों (ग्रुप ए/बी) द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके विभाग की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों, के बारे में अवगत कराया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे, लाइन विभाग के अधिकारियों को, निर्देशित चर्चा की सुविधा के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में, अपने विभागों से संबंधित मुद्दों/योजनाओं पर मानकीकृत प्रस्तुतीकरण भी करना आवश्यक है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण क्षेत्र के माध्यम से पहचाने गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के अंतराल के अस्तित्व पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इन अंतरालों को कैसे पाटना है, इसकी पहचान की जा सके।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि इन बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम 10% रखा जाए और इस कोरम के भीतर महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता न्यूनतम 30% रखी जाए। ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा / महिला सभा / बालसभा की बैठकों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अग्रिम रूप से पहचान की जा सके और ग्राम सभाओं के दौरान चर्चा के लिए लाया जा सके।

इसके अलावा, पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित किया गया है; और इस दिशा में, स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सहमत होंगे कि जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और निधियों को एक साथ लाने की (अभिसरण की) तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक जन योजना अभियान के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभाओं में विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया है।

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

(2)

आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड राज्य में, ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के 50%, पेयजल विभाग से 44%, पशुपालन विभाग से मात्र 6%, शिक्षा विभाग से 81%, ग्रामीण विकास विभाग से 81%, महिला एवं बाल विभाग से 44 %, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से 'शून्य', स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग से 56% जल संसाधन विभाग से 'शून्य' और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से 'शून्य' अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों ने भाग लिया। यह देखा जा सकता है कि ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों की भागीदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आप सहमत होंगे कि ऐसा अभिसरण जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तभी संभव होगा जब कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इससे न केवल ग्राम सभा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण आबादी में भी उत्साह और भागीदारी पैदा होगी जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

तदनुसार, यह अनुरोध है कि अपने राज्य के सभी संबंधित विभागों को ग्राम सभा की बैठकों में लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें, ताकि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(गिरिराज सिंह)

श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड
पहली मंजिल, प्रॉजेक्ट बिल्डिंग,
रांची, झारखंड।

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.संख्या-11015/98/2021-एफडी
दिनांक: 13 दिसंबर, 2021

आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी,
सादर नमस्कार,

सबसे पहले, मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

कृपया ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के विषय पर मेरे द्वारा दिनांक 20 सितंबर, 2021 को लिखे गये पत्र का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को राज्यों को एक व्यापक परामर्श जारी किया। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य रूप से द्विमासिक आवृत्ति पर न्यूनतम 6 बैठकें करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया था।

यह भी सहमति हुई थी कि ग्राम सभा की बैठकों में जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, के संबंध में विकास के लिए व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए; जिला/ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों (ग्रुप ए/बी) द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके विभाग की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों, के बारे में अवगत कराया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे, लाइन विभाग के अधिकारियों को, निर्देशित चर्चा की सुविधा के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में, अपने विभागों से संबंधित मुद्दों/योजनाओं पर मानकीकृत प्रस्तुतीकरण भी करना आवश्यक है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण क्षेत्र के माध्यम से पहचाने गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के अंतराल के अस्तित्व पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इन अंतरालों को कैसे पाटना है, इसकी पहचान की जा सके।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि इन बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम 10% रखा जाए और इस कोरम के भीतर महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता न्यूनतम 30% रखी जाए। ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा / महिला सभा / बालसभा की बैठकों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अग्रिम रूप से पहचान की जा सके और ग्राम सभाओं के दौरान चर्चा के लिए लाया जा सके।

इसके अलावा, पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित किया गया है; और इस दिशा में, स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सहमत होंगे कि जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और निधियों को एक साथ लाने की (अभिसरण की) तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक जन योजना अभियान के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभाओं में विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया है।

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

(2)

आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान राज्य में, ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के 56%, पेयजल विभाग से मात्र 16%, पशुपालन विभाग से मात्र 8%, शिक्षा विभाग से 85%, ग्रामीण विकास विभाग से मात्र 14%, महिला एवं बाल विभाग से 65 %, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से 34 %, स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग से 55% जल संसाधन विभाग से मात्र 2% और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से 'शून्य' अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों ने भाग लिया। यह देखा जा सकता है कि ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों की भागीदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आप सहमत होंगे कि ऐसा अभिसरण जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तभी संभव होगा जब कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इससे न केवल ग्राम सभा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण आबादी में भी उत्साह और भागीदारी पैदा होगी जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

तदनुसार, यह अनुरोध है कि अपने राज्य के सभी संबंधित विभागों को ग्राम सभा की बैठकों में लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें, ताकि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(गिरिराज सिंह)

श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
सीएमओ सचिवालय, जयपुर,
राजस्थान-302005

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.संख्या-11015/98/2021-एफडी
दिनांक: 13 दिसंबर, 2021

आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
सादर नमस्कार,

सबसे पहले, मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

कृपया ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के विषय पर मेरे द्वारा दिनांक 20 सितंबर, 2021 को लिखे गये पत्र का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को राज्यों को एक व्यापक परामर्श जारी किया। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य रूप से द्विमासिक आवृत्ति पर न्यूनतम 6 बैठकें करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया था।

यह भी सहमति हुई थी कि ग्राम सभा की बैठकों में जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, के संबंध में विकास के लिए व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए; जिला/ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों (ग्रुप ए/बी) द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके विभाग की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों, के बारे में अवगत कराया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे, लाइन विभाग के अधिकारियों को, निर्देशित चर्चा की सुविधा के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में, अपने विभागों से संबंधित मुद्दों/योजनाओं पर मानकीकृत प्रस्तुतीकरण भी करना आवश्यक है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण क्षेत्र के माध्यम से पहचाने गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के अंतराल के अस्तित्व पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इन अंतरालों को कैसे पाटना है, इसकी पहचान की जा सके।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि इन बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम 10% रखा जाए और इस कोरम के भीतर महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता न्यूनतम 30% रखी जाए। ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा / महिला सभा / बालसभा की बैठकों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अग्रिम रूप से पहचान की जा सके और ग्राम सभाओं के दौरान चर्चा के लिए लाया जा सके।

इसके अलावा, पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित किया गया है; और इस दिशा में, स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सहमत होंगे कि जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और निधियों को एक साथ लाने की (अभिसरण की) तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक जन योजना अभियान के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभाओं में विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया है।

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

(2)

आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश राज्य में, ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के 28%, पेयजल विभाग से मात्र 4%, पशुपालन विभाग से मात्र 7%, शिक्षा विभाग से 70%, ग्रामीण विकास विभाग से 44%, महिला एवं बाल विभाग से 72 %, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से 28 %, स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग से 53% जल संसाधन विभाग से मात्र 1% और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से 'शून्य' अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों ने भाग लिया। यह देखा जा सकता है कि ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों की भागीदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आप सहमत होंगे कि ऐसा अभिसरण जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तभी संभव होगा जब कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इससे न केवल ग्राम सभा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण आबादी में भी उत्साह और भागीदारी पैदा होगी जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

तदनुसार, यह अनुरोध है कि अपने राज्य के सभी संबंधित विभागों को ग्राम सभा की बैठकों में लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें, ताकि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(गिरिराज सिंह)

श्री शिवराज सिंह चौहान
माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
अरेरा हिल्स, एमपी नगर,
जहांगीराबाद, भोपाल,
मध्य प्रदेश-462008

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.संख्या-11015/98/2021-एफडी
दिनांक: 13 दिसंबर, 2021

आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी,
सादर नमस्कार.

सबसे पहले, मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

कृपया ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के विषय पर मेरे द्वारा दिनांक 20 सितंबर, 2021 को लिखे गये पत्र का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को राज्यों को एक व्यापक परामर्श जारी किया। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य रूप से द्विमासिक आवृत्ति पर न्यूनतम 6 बैठकें करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया था।

यह भी सहमति हुई थी कि ग्राम सभा की बैठकों में जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, के संबंध में विकास के लिए व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए; जिला/ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों (गुप ए/बी) द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके विभाग की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों, के बारे में अवगत कराया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे, लाइन विभाग के अधिकारियों को, निर्देशित चर्चा की सुविधा के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में, अपने विभागों से संबंधित मुद्दों/योजनाओं पर मानकीकृत प्रस्तुतीकरण भी करना आवश्यक है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण क्षेत्र के माध्यम से पहचाने गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के अंतराल के अस्तित्व पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इन अंतरालों को कैसे पाटना है, इसकी पहचान की जा सके।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि इन बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम 10% रखा जाए और इस कोरम के भीतर महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता न्यूनतम 30% रखी जाए। ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा / महिला सभा / बालसभा की बैठकों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अग्रिम रूप से पहचान की जा सके और ग्राम सभाओं के दौरान चर्चा के लिए लाया जा सके।

इसके अलावा, पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित किया गया है; और इस दिशा में, स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सहमत होंगे कि जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और निधियों को एक साथ लाने की (अभिसरण की) तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक जन योजना अभियान के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभाओं में विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया है।

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

(2)

आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार राज्य में, ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के 67%, पेयजल विभाग से मात्र 2%, पशुपालन विभाग से मात्र 3%, शिक्षा विभाग से 51%, ग्रामीण विकास विभाग से 56%, महिला एवं बाल विभाग से 40 %, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से मात्र 13 %, स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग से 33% जल संसाधन विभाग से 'शून्य' और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से 'शून्य' अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों ने भाग लिया। यह देखा जा सकता है कि ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों की भागीदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आप सहमत होंगे कि ऐसा अभिसरण जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तभी संभव होगा जब कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इससे न केवल ग्राम सभा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण आबादी में भी उत्साह और भागीदारी पैदा होगी, जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

तदनुसार, यह अनुरोध है कि अपने राज्य के सभी संबंधित विभागों को ग्राम सभा की बैठकों में लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें, ताकि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(गिरिराज सिंह)

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार
4, देशरत्न मार्ग,
पटना-800001

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.संख्या-11015/98/2021-एफडी
दिनांक: 13 दिसंबर, 2021

आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
सादर नमस्कार.

सबसे पहले, मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

कृपया ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के विषय पर मेरे द्वारा दिनांक 20 सितंबर, 2021 को लिखे गये पत्र का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को राज्यों को एक व्यापक परामर्श जारी किया। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य रूप से द्विमासिक आवृत्ति पर न्यूनतम 6 बैठकें करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया था।

यह भी सहमति हुई थी कि ग्राम सभा की बैठकों में जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, के संबंध में विकास के लिए व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए; जिला/ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों (ग्रुप ए/बी) द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके विभाग की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों, के बारे में अवगत कराया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे, लाइन विभाग के अधिकारियों को, निर्देशित चर्चा की सुविधा के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में, अपने विभागों से संबंधित मुद्दों/योजनाओं पर मानकीकृत प्रस्तुतीकरण भी करना आवश्यक है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण क्षेत्र के माध्यम से पहचाने गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के अंतराल के अस्तित्व पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इन अंतरालों को कैसे पाटना है, इसकी पहचान की जा सके।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि इन बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम 10% रखा जाए और इस कोरम के भीतर महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता न्यूनतम 30% रखी जाए। ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा / महिला सभा / बालसभा की बैठकों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अग्रिम रूप से पहचान की जा सके और ग्राम सभाओं के दौरान चर्चा के लिए लाया जा सके।

इसके अलावा, पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित किया गया है; और इस दिशा में, स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सहमत होंगे कि जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और निधियों को एक साथ लाने की (अभिसरण की) तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक जन योजना अभियान के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभाओं में विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया है।

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

(2)

आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में, ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के मात्र 10%, पेयजल विभाग से 'शून्य', पशुपालन विभाग से 0%, शिक्षा विभाग से 93%, ग्रामीण विकास विभाग से 36%, महिला एवं बाल विभाग से 85 %, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से मात्र 25 %, स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग से 64% जल संसाधन विभाग से 'शून्य' और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से 'शून्य' अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों ने भाग लिया। यह देखा जा सकता है कि ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों की भागीदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आप सहमत होंगे कि ऐसा अभिसरण जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तभी संभव होगा जब कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इससे न केवल ग्राम सभा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण आबादी में भी उत्साह और भागीदारी पैदा होगी जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

तदनुसार, यह अनुरोध है कि अपने राज्य के सभी संबंधित विभागों को ग्राम सभा की बैठकों में लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें, ताकि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

सादर,

भवदीय
(Signature)

(गिरिराज सिंह)

योगी आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
लाल बहादुर शास्त्री भवन,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.संख्या-11015/98/2021-एफडी
दिनांक: 13 दिसंबर, 2021

आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी,
सादर नमस्कार,

सबसे पहले, मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।

कृपया ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने के विषय पर मेरे द्वारा दिनांक 20 सितंबर, 2021 को लिखे गये पत्र का संदर्भ लें। जैसा कि आप जानते हैं, इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, पंचायती राज मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2021 को राज्यों को एक व्यापक परामर्श जारी किया। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य रूप से द्विमासिक आवृत्ति पर न्यूनतम 6 बैठकें करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया था।

यह भी सहमति हुई थी कि ग्राम सभा की बैठकों में जल-आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, के संबंध में विकास के लिए व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए; जिला/ब्लॉक स्तर पर लाइन विभाग के अधिकारियों (ग्रुप ए/बी) द्वारा अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिकों को उनके विभाग की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों, के बारे में अवगत कराया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे, लाइन विभाग के अधिकारियों को, निर्देशित चर्चा की सुविधा के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में, अपने विभागों से संबंधित मुद्दों/योजनाओं पर मानकीकृत प्रस्तुतीकरण भी करना आवश्यक है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण क्षेत्र के माध्यम से पहचाने गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे के अंतराल के अस्तित्व पर भी ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इन अंतरालों को कैसे पाटना है, इसकी पहचान की जा सके।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया गया था कि इन बैठकों के लिए न्यूनतम कोरम 10% रखा जाए और इस कोरम के भीतर महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता न्यूनतम 30% रखी जाए। ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा / महिला सभा / बालसभा की बैठकों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अग्रिम रूप से पहचान की जा सके और ग्राम सभाओं के दौरान चर्चा के लिए लाया जा सके।

इसके अलावा, पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित किया गया है; और इस दिशा में, स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सहमत होंगे कि जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और निधियों को एक साथ लाने की (अभिसरण की) तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक जन योजना अभियान के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभाओं में विभिन्न लाइन विभागों की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण किया है।

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

(2)

आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य में, ग्राम सभाओं में कृषि विभाग के 32%, पेयजल विभाग से 26%, पशुपालन विभाग से 24%, शिक्षा विभाग से मात्र 16%, ग्रामीण विकास विभाग से मात्र 13%, महिला एवं बाल विभाग से मात्र 12 %, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से मात्र 8 %, स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग से मात्र 4% जल संसाधन विभाग से 'शून्य' और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से 'शून्य' अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों ने भाग लिया। यह देखा जा सकता है कि ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों की भागीदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आप सहमत होंगे कि ऐसा अभिसरण जो ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तभी संभव होगा जब कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इससे न केवल ग्राम सभा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण आबादी में भी उत्साह और भागीदारी पैदा होगी जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

तदनुसार, यह अनुरोध है कि अपने राज्य के सभी संबंधित विभागों को ग्राम सभा की बैठकों में लाइन विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दें, ताकि स्थायी ग्रामीण विकास के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(गिरिराज सिंह)

श्री पुष्कर सिंह धामी

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड,
4 सुभाष रोड़, उत्तराखंड सचिवालय,
4वीं मंजिल, नया बिल्डिंग, देहरादून,
उत्तराखंड-248001

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri V. S. Jagannathan Reddy Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States/UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas / mahila sabhas / bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Andhra Pradesh, only 50% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 19% from Drinking Water Department, 25% from Animal Husbandry Department, 35% from Education Department, 21% from Rural Development Department, 51% from Women & Child Department, 24% from Health & Family Welfare Department, 55% from Health & Sanitation Department, 1% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Y.S. Jaganmohan Reddy
Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh
1st Floor, Building-I,
Velagapudi-2441521
Andhra Pradesh

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Pema Khandu Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas / bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Arunachal Pradesh, only 67% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 8% from Drinking Water Department, 18% from Animal Husbandry Department, 69% from Education Department, 45% from Rural Development Department, 28% from Women & Child Department, 15% from Health & Family Welfare Department, 35% from Health & Sanitation Department, 4% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Pema Khandu
Hon'ble Chief Minister of Arunachal Pradesh
The CM Secretariat, CM Bungalow,
NitiVihar, Itanagar-791111
Arunachal Pradesh

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Himanta Biswa Sharma Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Assam, only 51% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 6% from Drinking Water Department, 28% from Animal Husbandry Department, 27% from Education Department, 22% from Rural Development Department, 9% from Women & Child Department, 14% from Health & Family Welfare Department, 20% from Health & Sanitation Department, 3% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Himanta Biswa Sarma
Hon'ble Chief Minister of Assam
CM Block, Janata Bhawan,
Dispur-781006
Assam

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Bhupendra Rajnikant Patelji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

.....2/

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
 भारत सरकार
 कृषि भवन, नई दिल्ली
 MINISTER OF
 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
 GOVERNMENT OF INDIA
 KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Gujarat, only 64% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 11% from Drinking Water Department, 21% from Animal Husbandry Department, 43% from Education Department, 28% from Rural Development Department, 36% from Women & Child Department, 10% from Health & Family Welfare Department, 37% from Health & Sanitation Department, 'Nil' from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Bhupendra Rajnikant Patel
 Hon'ble Chief Minister of Gujarat
 3rd Floor, Swarnim Sankul-1
 New Sachivalaya,
 Gandhinagar 382010
Gujarat

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Basavaraj Bommai Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
 भारत सरकार
 कृषि भवन, नई दिल्ली
 MINISTER OF
 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
 GOVERNMENT OF INDIA
 KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Karnataka, only 34% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 15% from Drinking Water Department, 19% from Animal Husbandry Department, 53% from Education Department, 23% from Rural Development Department, 38% from Women & Child Department, 18% from Health & Family Welfare Department, 37% from Health & Sanitation Department, 1% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Basavaraj Bommai
 Hon'ble Chief Minister of Karnataka
 204, 2nd Floor, VidhanaSoudha,
 AmbedkarVidi, Bengaluru-560001
Karnataka

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Pinarayi Vijayan Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Kerala, only 84% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 'Nil' from Drinking Water Department, 81% from Animal Husbandry Department, 56% from Education Department, 60% from Rural Development Department, 26% from Women & Child Department, 12% from Health & Family Welfare Department, 68% from Health & Sanitation Department, 'Nil' from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Pinarayi Vijayan
Hon'ble Chief Minister of Kerala
Room No: 141, 3rd Floor, North Block,
Secretariat, Statue,
Thiruvananthapuram-695001

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Shri Uddhav Thackeray Ji,*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

.....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Maharashtra, only 54% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 30% from Drinking Water Department, 8% from Animal Husbandry Department, 61% from Education Department, 27% from Rural Development Department, 39% from Women & Child Department, 20% from Health & Family Welfare Department, 45% from Health & Sanitation Department, 3% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Uddhav Thackeray
Hon'ble Chief Minister of Maharashtra
Chief Minister's Office, 6th Floor,
Mantralaya,
Mumbai-400032
Maharashtra

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri N. Birun Singh Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

...2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
 भारत सरकार
 कृषि भवन, नई दिल्ली
 MINISTER OF
 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
 GOVERNMENT OF INDIA
 KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Manipur, only 66% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 'Nil' from Drinking Water Department, 46% from Animal Husbandry Department, 63% from Education Department, 23% from Rural Development Department, 'Nil' from Women & Child Department, 3% from Health & Family Welfare Department, 6% from Health & Sanitation Department, 'Nil' from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri N. Biren Singh
 Hon'ble Chief Minister of Manipur
 Manipur CM Office, 4th Floor, Western Block,
 New Secretariat, Imphal-795001
Manipur

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Conrad Kongkal Sangma Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Meghalaya, only 40% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 12% from Drinking Water Department, 40% from Animal Husbandry Department, 19% from Education Department, 73% from Rural Development Department, 12% from Women & Child Department, 10% from Health & Family Welfare Department, 25% from Health & Sanitation Department, 5% from Water Resources Department and 1% from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Conrad Kongkal Sangma
Hon'ble Chief Minister of Meghalaya
Meghalaya CM Office, Room No 401,
Yojana Bhawan, Shillong-797001
Meghalaya

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Shri Pt. Zoramthanga Ji.*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Mizoram, only 19% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 3% from Drinking Water Department, 14% from Animal Husbandry Department, 34% from Education Department, 40% from Rural Development Department, 12% from Women & Child Department, 27% from Health & Family Welfare Department, 7% from Health & Sanitation Department, 'Nil' from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Pu Zoramthanga
Hon'ble Chief Minister of Mizoram
Chief Ministers Bungalow, Mc Donald Hill,
Zarkawt, Aizawl-796001
Mizoram

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Shri Neelphik Rio Ji,*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Nagaland, only 17% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 8% from Drinking Water Department, 19% from Animal Husbandry Department, 53% from Education Department, 74% from Rural Development Department, 5% from Women & Child Department, 39% from Health & Family Welfare Department, 19% from Health & Sanitation Department, 7% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Neiphiu Rio
Hon'ble Chief Minister of Nagaland
Nagaland CM Office, New Secretariat Complex,
Kohima-797001
Nagaland

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Naveen Patnaik Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the-GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
 भारत सरकार
 कृषि भवन, नई दिल्ली
 MINISTER OF
 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ,
 GOVERNMENT OF INDIA
 KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Odisha, only 55% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 29% from Drinking Water Department, 18% from Animal Husbandry Department, 54% from Education Department, 'Nil' from Rural Development Department, 47% from Women & Child Department, 29% from Health & Family Welfare Department, 36% from Health & Sanitation Department, 1% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Naveen Patnaik
 Hon'ble Chief Minister of Odisha
 Odisha CM Office, Grievance Cell,
 Qrs No VIII-DS-I, Unit V,
 Bhubaneswar-751001
Odisha

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Shri Charanjit Singh Channi Ji,*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

...2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
 भारत सरकार
 कृषि भवन, नई दिल्ली
 MINISTER OF
 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
 GOVERNMENT OF INDIA
 KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Punjab, only 33% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 48% from Drinking Water Department, 5% from Animal Husbandry Department, 56% from Education Department, 64% from Rural Development Department, 59% from Women & Child Department, 25% from Health & Family Welfare Department, 41% from Health & Sanitation Department, 5% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Charanjit Singh Channi
 Hon'ble Chief Minister of Punjab
 Room No.1, 2nd floor,
 Punjab Civil Secretariat,
 Sector-1, Chandigarh-160001
Punjab

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Prem Singh Tamang Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
 भारत सरकार
 कृषि भवन, नई दिल्ली
 MINISTER OF
 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
 GOVERNMENT OF INDIA
 KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Sikkim, only 60% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 2% from Drinking Water Department, 22% from Animal Husbandry Department, 62% from Education Department, 55% from Rural Development Department, 4% from Women & Child Department, 8% from Health & Family Welfare Department, 17% from Health & Sanitation Department, 1% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Prem Singh Tamang
 Hon'ble Chief Minister of Sikkim
 Sikkim CM Office, Secretariat,
 Tashiling, Gangtok-737101
Sikkim

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Shri M.K. Stalin Ji,*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Tamil Nadu, only 37% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 14% from Drinking Water Department, 23% from Animal Husbandry Department, 78% from Education Department, 27% from Rural Development Department, 37% from Women & Child Department, 8% from Health & Family Welfare Department, 61% from Health & Sanitation Department, 1% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri M. K. Stalin
Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu
Chief Minister's Office Secretariat,
Chennai - 600 009
Tamil Nadu

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Admiral D.K. Joshi Ji,*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, only 90% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 2% from Drinking Water Department, 89% from Animal Husbandry Department, 80% from Education Department, 32% from Rural Development Department, 6% from Women & Child Department, 5% from Health & Family Welfare Department, 35% from Health & Sanitation Department, 2% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your Union Territory to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Admiral D K Joshi
Hon'ble Lt. Governor of Andaman & Nicobar Islands
UT of Andaman & Nicobar Islands,
Raj Niwas
Port Blair - 744101

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Shri K. Chandrasekhar Rao Ji,*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

...2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Telangana, only 45% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 20% from Drinking Water Department, 8% from Animal Husbandry Department, 72% from Education Department, 21% from Rural Development Department, 55% from Women & Child Department, 37% from Health & Family Welfare Department, 59% from Health & Sanitation Department, 2% from Water Resources Department and 1% from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri K Chandrasekhar Rao
Hon'ble Chief Minister of Telangana
Telangana CM Office, Secretariat,
Khairatabad,
Hyderabad - 500022
Telangana

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Shri Biplob Kumar Deb Ji,*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
 भारत सरकार
 कृषि भवन, नई दिल्ली
 MINISTER OF
 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
 GOVERNMENT OF INDIA
 KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Tripura, only 76% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 32% from Drinking Water Department, 51% from Animal Husbandry Department, 40% from Education Department, 62% from Rural Development Department, 10% from Women & Child Department, 19% from Health & Family Welfare Department, 24% from Health & Sanitation Department, 8% from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Biplab Kumar Deb
 Hon'ble Chief Minister of Tripura
 Tripura CM Office,
 Agartala-799001
Tripura

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Ms. Mamata Banerjee Ji,*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

•Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of West Bengal, only 29% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 16% from Drinking Water Department, 38% from Animal Husbandry Department, 70% from Education Department, 28% from Rural Development Department, 56% from Women & Child Department, 60% from Health & Family Welfare Department, 61% from Health & Sanitation Department, 4% from Water Resources Department and 1% from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Ms. Mamata Banerjee
Hon'ble Chief Minister of West Bengal
Nabanna, 325, Sarat Chatterjee Road,
Shibpur, Howrah-711101
West Bengal

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Manoj Sinha Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the Union Territory of Jammu & Kashmir, only 40% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 15% from Drinking Water Department, 25% from Animal Husbandry Department, 72% from Education Department, 48% from Rural Development Department, 23% from Women & Child Department, 21% from Health & Family Welfare Department, 54% from Health & Sanitation Department, 'Nil' from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your Union Territory to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Manoj Sinha
Hon'ble Lt. Governor of Jammu & Kashmir
UT of Jammu and Kashmir
Raj Bhawan, Gupkar Road
Srinagar - 190001

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Shri Radha Krishna Mathur Ji,
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the Union Territory of Ladakh, only 44% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 1% from Drinking Water Department, 17% from Animal Husbandry Department, 7% from Education Department, 11% from Rural Development Department, 34% from Women & Child Department, 2% from Health & Family Welfare Department, 33% from Health & Sanitation Department, 'Nil' from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your Union Territory to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Shri Radha Krishna Mathur
Hon'ble Lt. Governor of Ladakh
UT of Ladakh
UT Secretariat,
Raj Bhawan
Ladakh

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected *Shri Praful Patel Ji,*
Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States / UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas / mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign.

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
 भारत सरकार
 कृषि भवन, नई दिल्ली
 MINISTER OF
 RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
 GOVERNMENT OF INDIA
 KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the Union Territory of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, only 86% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 57% from Drinking Water Department, 100% from Animal Husbandry Department, 71% from Education Department, 71% from Rural Development Department, 71% from Women & Child Department, 86% from Health & Family Welfare Department, 86% from Health & Sanitation Department, 'Nil' from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your Union Territory to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,


 (GIRIRAJ SINGH)

Shri Praful Patel (Administrator)
 Hon'ble Administrator of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
 UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No.M-11015/98/2021-FD

13 December, 2021

Respected Dr. Pramod Samant Ji,

Namaskar,

At the outset, I convey my best regards and warm greetings to you.

Please refer to my earlier letter of dated 20th September, 2021 on the subject of Making Gram Sabhas Vibrant. As you are aware, after intensive consultations with the Panchayati Raj Departments of States/UTs and various experts/stakeholders on the subject, the Ministry of Panchayati Raj issued a comprehensive advisory to the States dated 16th August, 2021. The States/ UTs had committed for the Gram Panchayats to mandatorily have a minimum of 6 meetings at bi-monthly frequency.

It was agreed that the Gram Sabha meetings should have extensive deliberations for development with respect to the National focus areas of Water Supply, Sanitation, Health, Education and Nutrition. It was also agreed that the Gram Sabha meetings are to be necessarily attended by the line department officials (Group A / B) at the District/ Block level in order to apprise the rural citizens regarding their department's schemes of both Central and State Governments, with a view to ensure that the benefits of such schemes reach to all the needy citizens. The line department officials are also required to make standardized presentations on the issues / schemes concerning their respective departments in the Gram Sabha meetings in order to facilitate guided discussions. The existence of infrastructure gaps of the respective Gram Panchayats identified through the Mission Antyodaya survey area also to be discussed in the Gram Sabha meetings to identify as to how to bridge these gaps.

Further for ensuring the effectiveness of the Gram Sabhas meetings, it was suggested that the minimum quorum for these meetings is kept at 10% and within this quorum, the attendance requirement of women be kept at minimum 30%. The Gram Sabha meetings are also to be preceded by ward sabhas/ mahila sabhas/ bal sabha meetings, as required, so that their specific requirements are identified in advance and brought in for discussions during the Gram Sabhas.

Moreover, the Panchayats are constitutionally mandated under Article 243G for the preparation of plans and implementation of schemes for economic development and social justice; and towards this end, have been making Panchayat Development Plans to fulfill the local needs and aspirations. You would agree that there is an urgent need to converge the various schemes and funds through an active involvement of the line departments in the GPDP planning process. In this regard, the Ministry has carried out a detailed analysis of the participation of different line departments in the GPDP Gram Sabhas conducted as part of the annual People's Plan Campaign. -

....2/-

135073/2021/FD SECTION

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

-2-

The data reveals that in the State of Goa, 100% of Gram Sabhas were attended by frontline officials from Agriculture Department, 50% from Drinking Water Department, 50% from Animal Husbandry Department, 'Nil' from Education Department, 50% from Rural Development Department, 100% from Women & Child Department, 50% from Health & Family Welfare Department, 'Nil' from Health & Sanitation Department, 'Nil' from Water Resources Department and 'Nil' from New & Renewable Energy Department. It can be seen that there is large scope for improvement in the participation of frontline officials in the Gram Sabhas.

You would agree, that such convergence which is vital for the holistic development of the rural areas, would not be possible unless the line departments actively participate in the Gram Sabhas during the GPDP planning and implementation process, so as to fulfill the aspirations of the people. This would not only enhance the efficacy of the Gram Sabha, but also generate much enthusiasm and participation amongst the rural population.

It is accordingly requested to direct all concerned departments in your State to ensure the active participation of the frontline officials of the line departments and SHG members in the Gram Sabha meetings, so that the vision of "Atmanirbhar Bharat" can be realised for sustainable Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

Dr. Pramod Sawant
Hon'ble Chief Minister of Goa
Chief Minister Office,
House No. 12/182 Khorlim
Mapusa, Panaji-403507
Goa